

न्यूज़ डुडे

सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINES: NLEM) में संशोधन किया गया

- सरकार ने प्रस्तावित मूल्य सीमा के लिए सूची के अंतर्गत 39 नई औषधियों को शामिल करने हेतु NLEM को संशोधित किया है। यह संशोधन व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली आवश्यक औषधियों के मूल्यों को कम करने हेतु किया गया है।
 - वर्तमान में NLEM का वर्ष 2015 का संस्करण प्रचलन में है। ध्यातव्य है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 1996 से NLEM का प्रकाशन कर रहा है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के तहत विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई संशोधित सूची, स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तत्पश्चात् मंत्रालय अंतिम सूची को अधिसूचित करता है।
 - इससे पश्चात् सूची को वहनीय औषधियों और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति (Standing Committee on Affordable Medicines and Health Products: SCAMHP) को अर्पित किया जाता है। यह समिति यह आकलन करती है कि कौन-सी औषधियों के लिए मूल्य के सीमा-निर्धारण की आवश्यकता है।
 - SCAMHP मूल्य नियंत्रण के लिए औषधियों की अनुशंसा (स्वतः संज्ञान द्वारा भी) करने के लिए वर्ष 2019 में नीति आयोग के तहत गठित एक समिति है।
 - इससे पूर्व, NLEM के तहत सभी औषधियों के मूल्यों को सीमा निर्धारण के तहत रखा गया था।
 - वर्तमान में, यह SCAMHP की अनुशंसाओं के आधार पर चयनित रूप से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority: NPPA) द्वारा किया जाता है।
- NLEM में सूचीबद्ध औषधियों और उपकरणों को NPPA द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही विक्रय किया जाना चाहिए, जबकि गैर-अनुसूचित सूची में सूचीबद्ध औषधियों व उपकरणों हेतु अधिकतम 10% की वार्षिक मूल्य वृद्धि की अनुमति है।

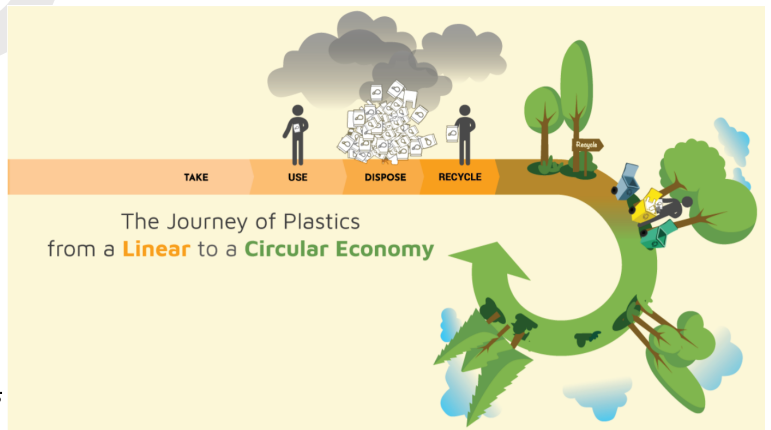


○ NPPA के बारे में

- इसे अगस्त, 1997 में औषध विभाग (DoP), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह औषधियों के मूल्य निर्धारण और वहनीय कीमतों पर औषधियों की उपलब्धता एवं उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया एक स्वतंत्र विनियामक है।

प्लास्टिक समझौते का शुभारंभ करने वाला भारत प्रथम एशियाई देश होगा

- इंडिया प्लास्टिक पैक्ट (IPP) को 16वें भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry: CII) के वार्षिक संधारणीयता शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड-वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF) और CII के मध्य सहयोग के रूप में लॉन्च किया गया है।
- IPP एक महत्वाकांक्षी व सहयोगात्मक पहल है। यह व्यवसायों, सरकारों, शोधकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को एक मंच प्रदान करती है।
 - IPP ने मौजूदा 'रैखिक प्लास्टिक प्रणाली' (linear plastics system) को 'चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था' (circular plastics economy) में परिवर्तित करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य-आधारित प्रतिबद्धताएं निर्धारित की हैं।
 - IPP को वैश्विक स्तर पर अन्य प्लास्टिक समझौतों से संबद्ध किया जाएगा।
 - इसका उद्देश्य, लक्ष्य और महत्वाकांक्षा एलेन मैकआर्थर फाउंडेशन की नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों के अनुरूप होना है।
 - प्रथम प्लास्टिक पैक्ट वर्ष 2018 में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था।



- IPP की आवश्यकता
 - भारत वार्षिक रूप से 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें से 40 प्रतिशत एकत्र नहीं किया जाता है।
 - वर्ष 2050 तक, प्लास्टिक जनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 56 गीगाटन से अधिक तक पहुंच सकता है, जो शेष कार्बन बजट का 10-13 प्रतिशत है।
- अन्य सरकारी पहलें
 - पोत परिवहन और मत्स्य पालन से उत्पन्न होने वाले समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट की रोकथाम एवं उसे कम करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप्स प्रोजेक्ट (GloLitter Partnerships Project) की शुरुआत की गई है।
 - भारत को वर्ष 2022 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है।
 - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 विशिष्ट एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं।
 - प्लास्टिक हैकथॉन 2021 अभियान का आयोजन भी किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्ति मामले में "प्रक्रिया के दुरुपयोग" के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका अस्वीकार की

○ उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भागीदारी के बिना स्वयं ही उसकी नियुक्ति करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना अस्वीकृत कर दिया है।

➤ पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी थी कि 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है और समिति का गठन करने के लिए UPSC को प्रदान की गई शक्ति, शासन के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है।

○ इससे पूर्व, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार (वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह वाद का निर्णय, जिसमें वर्ष 2018 में संशोधन किया गया) पर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह आदेश दिया था कि राज्यों को DGP पद के उम्मीदवारों के नाम UPSC को प्रेषित करना आवश्यक है। UPSC द्वारा वरिष्ठता, अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य नामों में से तीन उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

➤ इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा शीर्ष तीन उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन किया जाता है, किंतु नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम छह माह की सेवा-अवधि शेष होनी चाहिए।

○ प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ वाद

➤ न्यायालय ने पुलिस प्रणाली में गहराई तक स्थापित हो चुकी समस्याओं यथा- पुलिस का राजनीतिकरण, जवाबदेही तंत्र का अभाव और प्रणालीगत कमजोरियों का निराकरण करने के उद्देश्य से सात निर्देश (इन्फोग्राफिक देखें) जारी किए हैं। यह सर्वविदित है कि इन उल्लिखित समस्याओं के परिणामस्वरूप पुलिस के प्रदर्शन में गिरावट आई है एवं आम नागरिकों के बीच पुलिस व्यवस्था के प्रति असंतोष व्याप्त है।

भारत वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए तैयार है

○ 'इन्वेस्ट इंडिया' और पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) की पर्यावरण समिति द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2021: भारत के हाइड्रोजन इको सिस्टम को मजबूत करना' [International Climate Summit (ICS) 2021: powering India's Hydrogen Eco system] आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के भौगोलिक लाभ एवं क्षमताओं को रेखांकित किया गया।

➤ भारत द्वारा 'हाइड्रोजन-212' का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत 2 डॉलर प्रति किलोग्राम से कम होगी।

➤ ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय स्रोत [जैसे सौर फोटोवोल्टिक (PV) या पवन टरबाइन] द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन (electrolysis) के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।

○ हाइड्रोजन सर्वाधिक स्वच्छ ईंधनों में से एक है। इसका वायु में दहन करने पर उपोत्पाद के रूप में केवल जल उत्पन्न होता है और कोई कार्बन-आधारित उत्सर्जन मुक्त नहीं होता है।

➤ इसके संभावित अनुप्रयोगों में परिवहन, स्थायी विद्युत जैसे बैकअप पावर यूनिट और वहनीय अनुप्रयोग जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोरंजक उपकरण आदि शामिल हैं।

○ भारत में किए गए उपाय

➤ राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप का प्रवर्तन किया गया है।

➤ वर्ष 2020 में, दिल्ली हाइड्रोजन युक्त सी.एन.जी. के साथ बसें संचालित करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया था।

➤ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लेह में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना आरंभ की जाएगी।

➤ राष्ट्रीय जल विज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है।

○ सामना की जाने वाली चुनौतियां: उच्च उत्पादन लागत, भंडारण में कठिनाई, हाइड्रोजन की अत्यधिक ज्वलनशीलता, निम्न मांग के कारण उत्पादन क्षमता के विकास में बाधा आदि।

उच्चतम न्यायालय के सात निर्देश

- 1 राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए।
- 2 DGP को दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान किया जाए।
- 3 SPs और SHO's के लिए दो वर्ष का कार्यकाल निश्चित किया जाए।
- 4 जांच/अन्वेषण एवं कानून-व्यवस्था के कार्यों को पृथक किया जाए।
- 5 पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए।
- 6 राज्य और जिले स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किए जाएं।
- 7 केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए।



भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर-लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल (ALUAV) के लिए एक परियोजना-समझौते पर हस्ताक्षर किए

○ ALUAV के लिए परियोजना-समझौता रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (Defence Technology and Trade Initiative: DTTI) के अंतर्गत शामिल है।

➤ DTTI के तहत, परियोजनाओं की 2 श्रेणियां हैं:

i- उद्योग-से-उद्योग (industry-to-industry) परियोजनाओं से संबंधित, जिन्हें निर्यात लाइसेंस द्वारा सुगम बनाया गया है तथा

ii- वे परियोजनाएं, जिन्हें परियोजना-समझौतों (Project Agreements: PA) के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया गया है।

➤ ALUAV के लिए PA अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन (Research, Development] Testing and Evaluation: RDT & E) समझौते के तहत आरंभ की गई दूसरी श्रेणी की एक परियोजना है। इसे प्रथम बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था और जनवरी 2015 में नवीनीकृत किया गया था।

○ भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंध

➤ वर्ष 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। इसे वर्ष 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर-1 के दर्जे तक उन्नत कर दिया गया था।

➤ रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद आयोजित किया जाता है।

➤ भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के चार मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

➤ सैन्य सूचना के आदान-प्रदान पर वर्ष 2002 में जनरल सिक्वोरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)।

➤ वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA)।

➤ दोनों सेनाओं के मध्य अंतरसक्रियता और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए वर्ष 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्वोरिटी एग्रीमेंट (COMCASA)।

➤ उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए वर्ष 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)।

ग्रीन हाइड्रोजन
यह जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत-अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। इसमें

टर्क्योइज़ (Turquoise) हाइड्रोजन
CO₂ की बजाय मीथेन (मीथेन पायरोलिसिस) के तापीय विखंडन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन। टोस कार्बन का उत्पादन होता है।

येलो हाइड्रोजन
ग्रिड से प्राप्त विद्युत का उपयोग करके विद्युत-अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन।

ब्लू हाइड्रोजन
धूसर या भूरे रंग का ऐसा हाइड्रोजन, जिसकी CO₂ प्रचालित या पुनःप्रयोज्य हो।

पिंक/पर्पल/रेड हाइड्रोजन
परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत-अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन।

ब्लैक/ग्रे हाइड्रोजन
स्टीम-मीथेन रिफॉर्मिंग का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से निष्कर्षित हाइड्रोजन।

व्हाइट हाइड्रोजन
औद्योगिक प्रक्रियाओं के उपोत्पाद के रूप में उत्पादित हाइड्रोजन।

ब्राउन हाइड्रोजन
जीवाश्म ईंधन से निष्कर्षित हाइड्रोजन आमतौर पर गैसीकरण का उपयोग करके कोयले से निष्कर्षित की जाती है।

अन्य सुर्खियाँ

 पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum)	○ छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में, प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और रूस के मध्य प्रत्येक समय सुदृढ़ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। ○ पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में ➤ वर्ष 2015 में स्थापित, पूर्वी आर्थिक मंच ब्लादिवास्तोक (रूस) में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ➤ यह रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करता है। साथ ही, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार में मदद करता है। ➤ वर्ष 2019 में, भारत ने इसी मंच से अपनी 'एक्ट फार-ईस्ट' नीति को आरंभ किया था। इस नीति में इस संसाधन-समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 1 बिलियन यू.एस. डॉलर लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की गई थी।
 हंसा न्यू जनरेशन विमान (Hansa New Generation (NG) aircraft)	○ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research: CSIR)—राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (National Aerospace Laboratories: NAL), बेंगलुरु द्वारा हाल ही में डिजाइन एवं विकसित हंसा एनजी विमान ने सफलतापूर्वक अपनी प्रथम उड़ान भरी है। ➤ ऑल-कंपोजिट हंसा एनजी को वर्ष 2000 में नागर विमानन निदेशालय (DGCA) द्वारा ज्वाइंट एविएशन रिकवायरमेंट्स-वेरी लाइट एयरक्राफ्ट (JAR-VLA) श्रेणी के तहत प्रमाणित किया गया था। ○ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) ने प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए हंसा-एनजी के प्रेक्षक ग्राहक के रूप में CSIR-NAL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
 क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index (PMI))	○ हाल ही में जारी किए गए PMI ने विगत 18 महीनों में सेवा गतिविधियों में सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्षेप (rebound) को प्रदर्शित किया है। ○ PMI एक सर्वेक्षण-आधारित माप है। इसमें प्रत्यर्थियों से एक माह पूर्व से कुछ प्रमुख व्यावसायिक चरों के संबंध में उनकी मौजूदा धारणाओं में होने वाले परिवर्तन को लेकर प्रश्न किए जाते हैं। ➤ इसकी गणना विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक की जाती है और तत्पश्चात एक संयुक्त सूचकांक का निर्माण किया जाता है। ➤ PMI में 0 से 100 तक संख्याएं होती हैं। 50 से ऊपर PMI विस्तार को प्रदर्शित करता है, 50 से नीचे PMI संकुचन को दर्शाता है तथा 50 पर स्थिरता (कोई परिवर्तन नहीं) को प्रदर्शित करता है। ➤ PMI आंकड़ों को जापानी संस्था निक्केई (Nikkei) द्वारा प्रकाशित तथा मार्केट इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित एवं निर्मित किया जाता है।
 'शक्ति' (भारत में पारदर्शी ढंग से कोयले के दोहन एवं आवंटन की योजना) (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India (Shakti scheme))	○ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने शक्ति योजना के तहत विद्युत उत्पादन केंद्रों को एक की बजाय तीन पृथक-पृथक नीलामी विंडो के माध्यम से ईंधन खरीदने की अनुमति प्रदान की है। ○ महत्व ➤ इससे उत्पादकों को उनकी ईंधन खरीद और विद्युत की बिक्री की योजना के निर्माण हेतु लचीलापन प्राप्त होगा। ○ शक्ति योजना के बारे में— इसे वर्ष 2018 में उन तनावग्रस्त विद्युत इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था, जो कोयले की आपूर्ति के अभाव से ग्रसित थे। इस प्रकार यह विद्युत संयंत्रों को तनाव से बाहर निकलने में मदद करती है।
 नई बायो-मिथेनेशन प्रौद्योगिकियों का पहली बार प्रयोग	○ बायोमिथेनेशन एक जैविक प्रक्रिया है। इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्मजीवों की सहायता से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। ➤ महत्व— इसका उपयोग बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ○ प्रस्तुत की गई नई प्रौद्योगिकियां— एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर (स्थापित करने में सरल और उच्च बायोगैस का उत्पादन); नैनो फिल्ट्रेशन सेटअप (संदूषकों से मुक्त उत्तम गुणवत्ता युक्त जल के उत्पादन में कुशल)।
 विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22	○ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट की इस वर्ष की थीम "द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट: सोशल प्रोटेक्शन एट द क्रॉसरोड्स— इन परस्यूट ऑफ़ ए बेटर फ्यूचर" ○ मुख्य निष्कर्ष ➤ वर्तमान में, वैश्विक आबादी के केवल 47% लोगों को ही कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त है। ➤ कोविड-19 महामारी ने उच्च और निम्न आय स्तर वाले देशों के मध्य सामाजिक सुरक्षा अंतराल को प्रकट किया है और उसे बढ़ा दिया है। ➤ वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं।



थार रेगिस्तान में डायनासोर प्रजातियों के पदचिह्न मिले

- राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान में 3 डायनासोर प्रजातियों के पदचिह्न मिले हैं।
 - प्रारंभिक जुरासिक काल से संबंधित ये तीनों प्रजातियां मांसाहारी थीं।
- थार मरुस्थल विश्व की 18वीं सबसे बड़ी उपोष्णकटिबंधीय मरुभूमि है। साथ ही, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाली मरुभूमियों में से एक है, क्योंकि राजस्थान की 40 प्रतिशत मानव आबादी थार रेगिस्तान में निवासित है।
 - यह सतलज नदी तक विस्तारित है तथा विशाल कच्छ के रण, अरावली पर्वत और सिंधु नदी से घिरा हुआ है।



सुखियों में रहे स्थल

- **जापान**
 - हाल ही में, जापानी प्रधान मंत्री ने अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। जिसका अर्थ है कि वे प्रधान मंत्री पद का त्याग कर देंगे।
 - जापान को **निप्पॉन** या **उगते सूर्य की भूमि** भी कहा जाता है।
 - **प्रमुख जल निकाय**— जापान सागर, ओखोटस्क सागर, पूर्वी चीन सागर आदि
 - **प्रमुख द्वीप समूह**— चार मुख्य द्वीपों के रूप में **होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू**। होन्शू जापान का सबसे बड़ा द्वीप एवं मुख्य आर्थिक केंद्र है।
- **सीरिया**
 - हाल ही में, इजरायल ने सीरियाई भूमि से सक्रिय ईरान समर्थित विद्रोहियों से निपटने हेतु सीरिया पर हवाई हमले किए हैं।
 - **प्रमुख जल निकाय**— सीरिया भूमध्य सागर की पूर्वी सीमा पर स्थित है।
 - **यूफ्रेट्स या फ़रात** (तुर्की के पर्वतों से उद्गमित होने वाली) सीरिया की एक प्रमुख नदी है तथा बलख और खाबर इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
 - **सीमावर्ती देश**— तुर्की (उत्तर में), इराक (पूर्व में), जॉर्डन (दक्षिण में) और इजरायल एवं लेबनान (पश्चिम में)।
- **श्रीलंका**
 - विदेशी मुद्रा भंडार संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है।
 - **प्रमुख जल निकाय**— एडम्स ब्रिज (जिसे राम सेतु भी कहा जाता है) **मन्नार की खाड़ी** और **पाक जलडमरूमध्य** को पृथक करता है।
 - श्रीलंका की सबसे लंबी नदी **महावेली गंगा** को छोड़कर, अन्य सभी प्रमुख नदियाँ श्रीलंका की मध्य उच्च भूमि से अरीय प्रतिरूप में प्रवाहित होती हैं।
 - **अनूठी विशेषता**— श्रीलंका से गुजरने वाले अक्षांश **लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार** तथा **मालदीव द्वीप समूह** से भी होकर गुजरते हैं।



8468022022, 9019066066
www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi

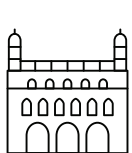
/Vision_IAS

/visionias_upsc

/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



लखनऊ



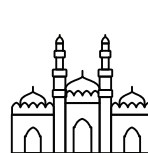
जयपुर



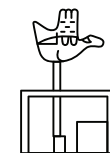
हैदराबाद



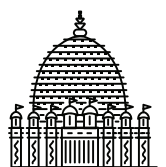
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी